

580

न्यायालय राजस्व मण्डल न्यायालय ग्वालियर (म.प्र.)

प्र.क ..... 2017 निगरानी

R 594-I-17

शिवनारायण पुत्र श्री भैयालाल दण्डोतिया  
निवासी खरी पाठक रोड विदिशा (म0प्र0)

.....!निगरानीकर्ता

बनाम

श्री. मन्दीव कुमल विदिशा  
द्वारा आज दि. 2-2-17 को  
प्रस्तुत

र.क.  
क्लक ऑफ कोर्ट 7-2-17  
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

1. रोशन लाल पुत्र श्री चुन्नी लाल अरोरा  
निवासी स्वर्णकार कॉलोनी विदिशा (म0प्र0)
2. श्रीमती हीरा बाई पत्नि जयराम गूजर  
निवासी मिर्जापुर तहसील व जिला विदिशा  
(म0प्र0)
3. नारायणी उर्फ शारदा बाई बेवा निहाल सिंह  
जाती गुर्जर (लिलोरिया)
4. धर्मदेव सिंह पुत्र रामधारी सिंह (फौत)  
बारिसान:
  - 4.1 इन्द्रासनी देवी पत्नि स्व. धर्मदेव सिंह
  - 4.2 दयाराम यादव पुत्र स्व. धर्मदेव सिंह  
निवासीगण--ग्राम मिर्जापुर तहसील विदिशा
  - 4.3 मनोज पुत्र स्व. धर्मदेव सिंह (फौत)
    - 4.3.1 पंकज यादव पुत्र स्व. मनोज यादव
    - 4.3.2 नीरज यादव पुत्र स्व. मनोज यादव  
नाबालिग सरपरसत ताऊ दयाराम यादव  
निवासी स्वर्णकार कॉलोनी विदिशा (म.प्र.)
  - 4.4 बच्चा यादव पुत्र धर्मदेव सिंह निवासी  
ग्राम मिर्जापुर तहसील व जिला विदिशा  
(म.प्र.)
  - 4.5 सोना यादव पुत्री स्व. धर्मदेव सिंह पत्नि  
अनुज यादव निवासी ग्राम दुपारिया तहसील  
व जिला विदिशा (म.प्र.)
5. कबिन्द्र सिंह पुत्र रामधारी सिंह यादव  
निवासी ग्राम मिर्जापुर तहसील व जिला  
विदिशा (म.प्र.)  
निवासीगण ग्राम दीघौरा तहसील ग्यारसपुर,  
जिला विदिशा (म0प्र0)

.....प्रतिनिगरानीकर्तागण

3

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 विरुद्ध आदेश दिनांकित 21.10.2016 जो प्रकरण क्रमांक 07/निग0/15-16 में न्यायालय अपर कलेक्टर महोदय, विदिशा जिला-विदिशा म0प्र0 द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत है।

निगरानीकर्ता की ओर से निगरानी सादर निम्नानुसार प्रस्तुत है:-


1. यहकि, प्रतिनिगरानीकर्तागण क्रमांक 03 लगायत 05 द्वारा अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार विदिशा के प्रकरण क्रमांक 12/अ-6-अ/1994-95 में पारित आदेश दिनांक 26.07.1995 के विरुद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत इस आशय की निगरानी प्रस्तुत की गई कि प्रतिनिगरानीकर्तागण क्रमांक 03 लगायत 05 ग्राम मिर्जापुर पटवारी हल्का न0-47 तहसील व जिला विदिशा के स्थाई निवासी होकर कृषक हैं। ग्राम मिर्जापुर स्थित भूमि क्रमांक 157 में निम्न कृषक हैं। भूमि क्रमांक 157 में से भूमि क्रमांक 157/1/1 मिन रकवा 4.181 हेक्ट0 की प्रार्थिया क्रमांक 1, भूमि क्रमांक 157/1/2 मिन रकवा 2.206 हेक्ट0 व भूमि क्रमांक 157/2/1 मिन रकवा 0.256 हेक्ट0 भूमि का प्रार्थी क्रमांक 2 भूमि क्रमांक 157/1/4 मिन रकवा 2.926 हेक्ट0 का प्रार्थी क्रमांक 3 एवं भूमि क्रमांक 157/1/5 रकवा 0.209 हेक्ट0 का प्रतिप्रार्थी क्रमांक 2, भूमि क्रमांक 157/2/2 रकवा 0.256 हेक्ट0 एवं भूमि क्रमांक 157/1/3 रकवा 0.209 हेक्ट0 की प्रतिप्रार्थी क्रमांक 3 भूमि स्वामी होकर मालिक काबिज है व मौके पर प्रत्येक काश्तकारान की पृथक पृथक मेडे डली हुई है व प्रथम प्रथम काश्त करते चले आ रहे हैं। ग्राम के नक्शे में सर्वे नंबर 157 के वटान नहीं थे इसलिये प्रार्थीगण एवं प्रतिप्रार्थीगण ने संयुक्त रूप से आपसी सहमति से न्यायालय नायब तहसीलदार तहसील विदिशा के प्रकरण क्रमांक 83/अ-3/1992-93 में पारित आदेश दिनांक 23.12.1993 द्वारा वटान कराकर वटान स्वीकार किया जाकर नक्शे में वटान अमल हो गये। प्रतिप्रार्थी क्रमांक 1 शिवनारायण ने न जाने कब वाला-वाला तहसीलदार विदिशा के यहाँ आवेदनपत्र प्रस्तुत कर उक्त वटान अमल में संशोधन करने हेतु आवेदनपत्र प्रस्तुत किया इस पर न्यायालय तहसीलदार विदिशा ने अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर प्रकरण क्रमांक 12/अ-6-अ/1994-95 दर्ज कर लिया। इस प्रकरण कार्यवाही में प्रार्थीगण व अन्य हितबद्ध पक्षकारों को पक्षकार नहीं बनाकर जानबूझकर म0प्र0 शासन को पक्षकार बनाया एवं वगैर प्रार्थीगण हितबद्ध पक्षकारान को सुनवाई का अवसर दिये वगैर फर्द वटवारा बुलाये वगैर एकपक्षीय रूप से मनमाने ढंग से दो वर्ष बाद पूर्व के नायब तहसीलदार विदिशा के आदेश दिनांकित 23.12.1993 को

## राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

## अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-594-एक/17

जिला - विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
19.12.18	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री संजीव मिश्रा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अपर कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24.4.19 को आयुक्त भोपाल संभाग भोपाल के समक्ष उपस्थित हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>प्रशासकीय सदस्य</b> </p> <p style="text-align: center;">3</p>	